



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2533]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2017/भाद्र 11, 1939

No. 2533]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2017/BHADRA 11, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

का.आ. 2892(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) समाज के विभिन्न वर्गों के लिए श्रम संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने हेतु **बी.बी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा को अनुदान दे रहा है;**

और, बी.बी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (जिसे इसमें इसके पश्चात् एजेंसी कहा गया है) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों के अधीन प्रतिभागियों में (i) श्रम प्रशासक और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्य पदधारियों, (ii) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के पदधारियों, (iii) श्रमिक संघ नेता और संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के आयोजकों, (iv) शोधकर्ताओं, (v) प्रशिक्षकों, (vi) क्षेत्रीय कामगारों और (vii) अन्य व्यक्ति जिनका संबंध श्रम संबंधी मुद्दों से है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशिक्षणार्थी कहा गया है):-

और, जिन्हें अनुमोदित दर पर उनकी हकदारियों के अनुसार उसके यात्रा भत्ता बिलों की प्रतिपूर्ति की जाती है और स्कीम में अतिथि संकायों जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान देते हैं उनको मानदेय तथा वाहन भत्ता के भुगतान हेतु सहायता अनुदान का भी प्रावधान है; (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशिक्षणार्थी और अतिथि संकाय को मिलाकर स्कीम के अधीन फायदाग्राही के रूप कहा गया है; तथा प्रशिक्षणार्थी के वाहन भत्ता की प्रतिपूर्ति और अतिथि संकायों को मानदेय तथा वाहन प्रभारों के भुगतान को मिलाकर स्कीम के अधीन फायदा कहा गया है);

और, उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्बलित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या के रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार प्रमाण प्रक्रिया पूरी करें।
- (2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उस दशा में वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो तो उससे प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से बीस दिन पहले आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी, और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन हेतु किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।
- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय का अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से, यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है उनके लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की प्रस्थापना करें और उस दशा में जहां ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीआईआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा;

परंतु स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आधार समनुदेशित किए जाने तक निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जा सकेंगी, अर्थात्:-

- (क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है; तो आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या
- (ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रतिलिपि; और
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-
- (i) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड या ;
- (ii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
- (iii) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके सरकारी पत्र-शीर्ष पर जारी फोटो सहित ऐसे व्यक्तियों का पहचान प्रमाण-पत्र या ;
- (iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या
- (v) पासपोर्ट; या
- (vi) राशन-कार्ड; या
- (vii) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा डाकघर पासबुक; या
- (viii) राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा विशिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

- (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया तथा व्यक्ति सूचनाएं देने के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, और यदि उन्होंने

पहले से नामांकन नहीं कराया है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसके लिए उन्हें नामनिर्दिष्ट अथवा चयनित किया गया हो, उसके आरम्भ होने से बीस दिन पूर्व उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय विद्यमान नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

- (2) यदि इस स्कीम के अधीन फायदाग्रही अपने आसपास में जैसे ब्लॉक अथवा तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्रों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो यह मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुगम स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तथा फायदाग्रही इस मंत्रालय के अभिहित अधिकारियों या कार्यान्वयन एजेंसी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्रदान किए गए वेबपोर्टल के माध्यम से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य विवरण देकर अपने नामांकन हेतु आवेदन रजिस्टर करा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू प्रभावी।

[फा. सं. क्यू-12019/1/2017-इएसए(एनएलआई)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2017

S.O. 2892(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is giving **grants to V.V. Giri National Labour Institute, Noida** for organising training and education programmes on labour issues for different segments of the society (*hereinafter referred to as the Scheme*);

And whereas, participants under the training and education programmes organised by the V.V. Giri National Labour Institute, Noida (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*) includes (i) Labour Administrators and other officials of the Central and State Governments, (ii) Officials of the Public and Private Sector Industries, (iii) Trade Union Leaders and Organisers of the organised and unorganised sectors, (iv) Researchers, (v) Trainers, (vi) Field Workers, and (vii) other persons who are concerned with labour issues (*hereinafter referred to as the trainees*):-

And whereas, who are given reimbursement of their travelling allowance bills as per their entitlements on approved rate and the Scheme also provides for grant-in-aid for payment of honorarium and conveyance to the guest faculties who deliver lectures in the training programmes; (Hereinafter, the trainees and the guest faculties together are referred to as the beneficiaries under the Scheme; and re-imbursement of travelling allowance of the trainees and payment of honorarium and conveyance charges to the guest faculties, together are referred to as the benefits under the Scheme).

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government in the Ministry of Labour and Employment notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) An individual desirous of receiving the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or who has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment before twenty days from commencement of the training programme, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at (www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he or she has enrolled for Aadhaar, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) A copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) any one of the following documents, namely:-
 - (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or
 - (ii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (iii) Certificate of identity having photo of such individual issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an Official Letter Head; or
 - (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or
 - (v) Passport; or
 - (vi) Ration Card; or
 - (vii) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo; or
 - (viii) Any other document specified by Ministry or Union Territory:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

- (1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefit under the Scheme and, in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar Enrolment Centre available in their areas before twenty days from the commencement of the training programme for which they have been nominated or selected and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
- (2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres within their vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and beneficiaries may register their requests for enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the

designated officials of the Ministry or the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territory Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. Q-12019/1/2017-ESA(NLI)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.